आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 15 लखनऊ, मंगलवार 21 जुलाई 2026 सा 27 जुलाई 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

E20 पेट्रोल से इंजन फेल होने का कोई प्रमाण नहीं: सरकार

E20 पेट्रोल पर सरकार का संसद में जवाब, इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव के दावों को बताया निराधार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि २० प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (**E20**) के उपयोग से वाहनों के इंजन या अन्य पुर्जों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दावों की व्यापक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने कहा कि **E20** कार्यक्रम को लागू करने से पहले व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण, तकनीकी मूल्यांकन और विशेषज्ञ संस्थानों से परामर्श किया गया था। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि भारत ने म्२० मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा से लगभग पांच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में नीति आयोग, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (**SIAM**), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (**ARAI**), ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (**OMCs**) तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (**IIP**) सहित कई विशेषज्ञ संस्थानों की भागीदारी रही। सरकार के अनुसार, वर्ष २०१४–१५ से अब

तक एथेन ल मिश्रण कार्यक्रम के चलते १.६७ लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसके साथ ही ३१६ लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात का विकल्प, ६५२ लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड (**CO2**) उत्सर्जन में कमी तथा किसानों को १.६६ लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है। सरकार ने कहा कि **E20** ईंधन के उपयोग से इंजन फेल होने, फ्यूल पंप खराब होने, जंग लगने, पानी से संबंधित समस्याएं या वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव जैसी शिकायतों की कोई व्यापक या प्रमाणित जानकारी वाहन निर्माताओं, ऑटोमोबाइल उद्योग संगठनों अथवा उपभोक्ता संगठनों से प्राप्त नहीं हुई है। सरकार ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर सामने आई आशंकाओं का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण कराया गया, लेकिन इन दावों की व्यापक पुष्टि नहीं हो सकी। सरकार का कहना है कि एथेन ल मिश्रण कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है।

हर शिकायत का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ।'' मुख्यमंत्री ''योगी आदित्यनाथ'' ने सोमवार को अपने सरकारी आवास ''५, कालिदास मार्ग'' पर आयोजित ''जनता दरबार'' में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने एक–एक कर लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों एवं मांगों की जानकारी ली। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का ''समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण'' सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए

तथा शिकायतों के समाधान में संवेदनशीलता और जवाबदेही बनाए रखी जाए। मुख्यमंत्री का जनता दरबार प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल माना जाता है।

निपुण भारत मिशन के विस्तारीकरण और लक्ष्य निर्धारण पर जोर, हर परिषदीय विद्यालय में लगेंगे निपुण लक्ष्य पोस्टर

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में लक्ष्य आधारित शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने निपुण भारत मिशन के तहत बड़ा कदम उठाया है। विभाग द्वारा ३१ जुलाई तक प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की सभी कक्षाओं में संबंधित कक्षा के निपुण लक्ष्य पोस्टर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी बीआरसी, बीएसए कार्यालय और डायट में भी इनका प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य बालवाटिका से कक्षा–५ तक प्रत्येक विद्यार्थी के लिए तय अधिगम लक्ष्यों को विद्यालय की दैनिक शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। निपुण लक्ष्य पोस्टर के प्रदर्शन को निरीक्षण व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। सपोर्टिव सुपरविजन ऐप और निरीक्षण ऐप में पोस्टर प्रदर्शन से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही निपुण संकल्प कार्यशालाओं तथा सभी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निपुण लक्ष्यों पर गहन चर्चा होगी। शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को भी इन लक्ष्यों के

प्रति लगातार जागरूक और प्रेरित किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर पोस्टर का प्रदर्शन टीएलएम अनुदान से कराया जाएगा। निपुण लक्ष्य चार्ट में बालवाटिका से कक्षा–५ तक प्रत्येक कक्षा के लिए विषयवार अधिगम परिणाम निर्धारित किए गए हैं। बालवाटिका में बच्चों के लिए दो से तीन अक्षर वाले सरल शब्द पढ़ने, अपना नाम पहचानने और लिखने तथा एक अंकीय संख्याओं की पहचान जैसे लक्ष्य तय किए गए हैं। कक्षा–१ और २ में छोटे वाक्य पढ़ने–लिखने, गिनती, जोड़–घटाव और दैनिक जीवन में मुद्रा के उपयोग जैसी दक्षताओं पर जोर दिया गया है। वहीं कक्षा–३ से ५ के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में अज्ञात गद्यांश को समझकर पढ़ना और उससे संबंधित कम से कम ७५ प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देना, स्वतंत्र लेखन, गणित में गुणा, भाग, भिन्न, ज्यामितीय ओंतियों की समझ, पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी व्यावहारिक अवधारणाओं तथा अंग्रेजी में समझ के साथ पढ़ने और लिखने के स्पष्ट अधिगम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। विभाग का मानना है कि इन मानकों के आधार पर शिक्षक प्रत्येक बच्चे की सीखने की प्रगति का आकलन कर सकेंगे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग भी दे सकेंगे।

जवाहर भवन में भीषण आग, एक घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबूय बड़ी जनहानि टली

लखनऊ। राजधानी के प्रमुख शासकीय भवनों में शामिल जवाहर भवन में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार सुबह ६:५३ बजे जवाहर भवन में आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन हजरतगंज से तीन अग्निशमन वाहन तत्काल मौके के लिए रवाना किए गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के अन्य फायर स्टेशनों से भी दमकल वाहनों को घटनास्थल भेजा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग जवाहर भवन के पिछले हिस्से में स्थित चौथी मंजिल के एक कार्यालय में लगी थी। आग तेजी से फैलने की आशंका के बीच दमकल कर्मियों ने समन्वित रणनीति अपनाते हुए समय रहते लपटों पर नियंत्रण पा लिया, जिससे आग भवन के अन्य हिस्सों तक नहीं पहुंच सकी। अभियान के दौरान कुल १५ अग्निशमन

वाहन मौके पर तैनात रहे। दमकल कर्मियों ने लगातार अभियान चलाकर आग को पूरी तरह बुझाया और भवन को सुरक्षित किया। अधिकारियों के अनुसार घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय की व्यापक सराहना की जा रही है, जिसने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर संभावित बड़े नुकसान को टाल दिया।

सम्पादकीय

कागजों में 'सरप्लस' शिक्षक, स्कूलों में शिक्षा का संकटः क्या छात्र संख्या का गणित बच्चों का भविष्य तय करेगा?

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में ३० हजार से अधिक शिक्षकों को 'सरप्लस' घोषित किए जाने की प्रक्रिया ने शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग १६ हजार शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों तथा करीब ११ हजार शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक बताए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि हजारों शिक्षक वास्तव में सरप्लस हैं, तो प्रदेश के अनेक विद्यालय आज भी एकल शिक्षक व्यवस्था पर क्यों चल रहे हैं? आखिर वे कौन–से विद्यालय हैं जहां शिक्षक अधिक हैं और वे कौन–से विद्यालय हैं जहां बच्चों को पढ़ाने वाला पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है? दरअसल, समस्या शिक्षकों की संख्या से अधिक उन मानकों की है जिनके आधार पर शिक्षक आवश्यकता तय की जा रही है। वर्तमान व्यवस्था में ३० विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, ६० पर दो और ९० विद्यार्थियों पर तीन शिक्षक पर्याप्त माने जा रहे हैं। यह गणित कागजों पर भले संतुलित दिखाई देता हो, लेकिन शिक्षा की वास्तविक जरूरतों से इसका मेल नहीं बैठता। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा १ से ५ तक के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम, सीखने का स्तर और शिक्षण पद्धति अलग होती है। कक्षा एक के बच्चों को अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो कक्षा पांच के विद्यार्थी विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों की जटिल अवधारणाएं सीख रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूरे विद्यालय में केवल एक या दो शिक्षक हों, तो उनसे सभी कक्षाओं को समान गुणवत्ता के साथ पढ़ाने की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। स्थिति उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। कक्षा ६, ७ और ८ में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। इन विषयों के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यदि सीमित संख्या में शिक्षक उपलब्ध होंगे, तो गुणवत्तापूर्ण विषय शिक्षण प्रभावित होना स्वाभाविक है। वास्तविकता यह भी है कि सरकारी शिक्षक केवल शिक्षण कार्य तक सीमित नहीं हैं। जनगणना, चुनाव, विभिन्न सर्वेक्षण, आधार सत्यापन, डीबीटी, छात्रवृत्ति, पोर्टल पर अ नलाइन फीडिंग, विभागीय प्रशिक्षण, बैठकों और अनेक प्रशासनिक कार्यों में उनकी नियमित भागीदारी रहती है। ऐसे में यदि किसी विद्यालय में पहले से ही सीमित शिक्षक हों और उनमें से भी किसी को गैर–शैक्षणिक कार्यों में भेज दिया जाए, तो विद्यालय में पढ़ाई लगभग ठप हो जाती है। यही कारण है कि कई अभिभावक सरकारी विद्यालयों की बजाय निजी विद्यालयों का रुख करते हैं। निजी विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए अलग शिक्षक, विषयवार शिक्षण व्यवस्था, कार्यालयी स्टाफ तथा गैर–शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं। इसके विपरीत सरकारी विद्यालयों में एक शिक्षक को कई कक्षाएं संभालने के साथ–साथ प्रशासनिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। इसके बावजूद दोनों व्यवस्थाओं के परिणामों की तुलना की जाती है, जो स्वाभाविक रूप से संतुलित नहीं कही जा सकती। शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि शिक्षा केवल छात्र संख्या का गणित नहीं है। प्रत्येक कक्षा को नियमित शिक्षक, प्रत्येक विषय को पर्याप्त समय और प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत शैक्षणिक सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षक उपलब्धता का निर्धारण केवल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर होगा, तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होना तय है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक तैनाती के मानकों की व्यापक समीक्षा की जाए। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक सुनिश्चित किया जाए, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था हो। साथ ही शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्यों से यथासंभव मुक्त कर उनका अधिकतम समय शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाए। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने के लिए केवल आंकड़ों में संतुलन दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होगी कि कक्षा में बच्चों को कितना प्रभावी शिक्षण मिल रहा है, न कि इस आधार पर कि कागजों में कितने शिक्षक 'सरप्लस' दिखाई दे रहे हैं। ''यदि शिक्षा को वास्तव में मजबूत बनाना है, तो शिक्षक को संख्या नहीं, संसाधन मानना होगा। अन्यथा कागजों में शिक्षक सरप्लस घोषित होते रहेंगे और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लगातार घाटे का सौदा बनती जाएगी।

विश्वास पर चोट और खोखली व्यवस्था

राकेश पाण्डेय 'निश्छल'

अयोध्या के भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे और आभूषणों में गड़बड़ी का मामला केवल कुछ छोटे कर्मचारियों की लालच या साधारण चोरी तक सीमित नहीं है। विशेष जांच दल **(SIT)** की परत–दर–परत खुलती पड़ताल यह साफ इशारा कर रही है कि यह देश के करोड़ों सनातनी आस्थावानों के अटूट विश्वास पर एक बहुत बड़ा आघात है। जो मंदिर परिसर देश की अस्मिता और भक्ति का केंद्र है, वहां से श्रद्धालुओं की दी हुई चांदी की चरण पादुकाएं और रत्नों से जड़े हार गायब हो जाएं और उनका कोई रिकॉर्ड तक न मिले, यह बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। इस पूरे प्रकरण ने देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक **(SBI)** की साख और उसकी सुरक्षा–प्रक्रिया पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जब बैंक के आला अधिकारियों ने मंदिर के चढ़ावे और चंदे की पाई–पाई सुरक्षित रखने का विस्तृत एमओयू **(MoU)** किया था, दानपात्रों की चाबियां बैंक के पास थीं, तो फिर यह सेंधमारी कैसे संभव हुई? यदि बैंक ने गणना के लिए किसी तीसरी एजेंसी (जैसे टीसीएस) को शामिल किया था, तो उसकी निगरानी और सत्यापन की जवाबदेही किसकी थी? बैंक और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच समन्वय की यह ढील इस बात का प्रमाण है कि नियम केवल कागजों तक सीमित रह गए थे। सबसे अधिक निराशाजनक पहलू मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट की सामूहिक जवाबदेही का पूरी तरह फेल होना है। प्रधानमंत्री के दूत माने जाने वाले निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य रसूखदार न्यासियों की नाक के नीचे छह साल से लूट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, लेकिन उनकी आंखें तब खुलीं जब कलंक का टीका माथे पर लग चुका था। सेवानिवृत्त इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के बयानों और जौनपुर के कारोबारी अजय विश्वकर्मा जैसे भुक्तभोगियों के दावों ने यह साबित कर दिया है कि निगरानी व्यवस्था में गंभीर 'सिस्टमैटिक फेलियर' (संस्थागत विफलता) था। एसआईटी की जांच अब अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी जाने वाली है। सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों के मिलान से असली गुनहगारों के चेहरे बेनकाब होना तय है। लेकिन इस जांच का असल मकसद केवल कुछ चेहरों को जेल भेजना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समूची व्यवस्था का कायाकल्प करना होना चाहिए जिसने इस पवित्र परिसर को दागदार किया। रामलला का दरबार पारदर्शिता और सुचिता का प्रतीक होना चाहिए, न कि प्रशासनिक लापरवाही और संस्थागत गैर–जिम्मेदारी का।

मोबाइल, माइक्रोफोन और 'तुरंत पत्रकार' की फैक्ट्रीः क्या पत्रकारिता प्रशिक्षण से नहीं, सिर्फ उपकरणों से तय होगी?

राकेश पाण्डेय 'निश्छल'

पत्रकारिता केवल खबर लिखने का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की चेतना, समाज का दर्पण और सत्ता से जवाबदेही मांगने का सबसे प्रभावी औजार है। लेकिन डिजिटल युग की तेज रफ्तार ने इस पेशे को जितनी नई संभावनाएं दी हैं, उतनी ही गंभीर चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। आज स्थिति यह है कि कभी पत्रकार बनने के लिए वर्षों का प्रशिक्षण, संपादकीय अनुशासन और समाचार की समझ जरूरी मानी जाती थी, जबकि अब कई लोग केवल एक मोबाइल फोन, माइक्रोफोन और सोशल मीडिया अकाउंट के सहारे स्वयं को पत्रकार घोषित कर देते हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी कि 'आज मोबाइल और माइक्रोफोन लेकर कोई भी स्वयं को पत्रकार घोषित कर सकता है' केवल एक न्यायिक टिप्पणी नहीं, बल्कि वर्तमान पत्रकारिता की बदलती तस्वीर पर गंभीर चिंतन का विषय है। यह टिप्पणी उस वास्तविकता को सामने लाती है, जिसमें पत्रकारिता का पेशा तेजी से पेशेवर प्रशिक्षण से हटकर तात्कालिक लोकप्रियता की ओर बढ़ता दिखाई देता है। एक समय था जब छोटे–छोटे स्थानीय समाचार पत्र पत्रकारिता की प्रयोगशाला हुआ करते थे। वहां प्रशिक्षु संवाददाता अपनी पहली खबर लेकर संपादक के सामने बैठता था। संपादक केवल खबर नहीं सुधारता था, बल्कि संवाददाता की सोच, भाषा, तथ्य और दृष्टिकोण को भी गढ़ता था। एक–एक शब्द की शुद्धता, तथ्यों की पुष्टि और प्रस्तुति की मर्यादा वहीं सिखाई जाती थी। पत्रकारिता किसी विश्वविद्यालय से कम और संपादक की लाल स्याही से अधिक सीखी जाती थी। प्रशिक्षु संवाददाता समाचार लिखने के साथ कंपोजिंग करता, प्रूफ पढ़ता, मशीन के पास खड़ा रहता और अखबार छपने तक पूरी प्रक्रिया को समझता था। उस दौर में पत्रकारिता का प्रमाण–पत्र कोई पहचान पत्र नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और सीखने की निरंतर प्रक्रिया होती थी। यही कारण था कि छोटे समाचार पत्रों की स्याही से निकले अनेक पत्रकार आगे चलकर राष्ट्रीय समाचार पत्रों और बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों तक पहुंचे। फिर तकनीक ने दस्तक दी। कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया और उसके बाद स्मार्टफोन ने पूरी दुनिया को हथेली पर ला दिया। तकनीक ने पत्रकारिता को गति, विस्तार और नई शक्ति दी, लेकिन इसके साथ एक नई समस्या भी पैदा हुई बिना प्रशिक्षण के पत्रकार बनने की जल्दबाजी। आज अनेक स्थानों पर पत्रकारिता सीखने का पहला प्रश्न यह नहीं होता कि 'समाचार कैसे लिखा जाए?'बल्कि यह होता है कि 'विज्ञापन पर कितना कमीशन मिलेगा?' ज्ञान की जगह कमाई की गणना और जनहित की जगह प्रचार ने धीरे–धीरे अपनी जगह बना ली। परिणामस्वरूप कई जगह संवाददाता कम और विज्ञापन–संग्रहकर्ता अधिक तैयार होने लगे। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया। अब न संपादकीय मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस होती है, न तथ्य–जांच की चिंता और न ही समाचार की पुष्टि का धैर्य। जेब में मोबाइल, हाथ में माइक्रोफोन और सोशल मीडिया पर एक पेज बनते ही कई लोग स्वयं को वरिष्ठ पत्रकार घोषित कर देते हैं। सुबह किसी नेता का गुणगान, दोपहर में किसी अधिकारी का लाइव प्रसारण और शाम को किसी व्यापारी का प्रचार इसे ही 'ब्रेकिंग न्यूज' का नाम दे दिया जाता है। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि समस्या मोबाइल फोन या सोशल मीडिया नहीं है। तकनीक स्वयं कभी दोषी नहीं होती। दोष उस सोच का है, जिसने उपकरणों को ही पत्रकारिता मान लिया। कैमरा दृश्य दिखा सकता है, लेकिन दृष्टि नहीं दे सकता। माइक्रोफोन आवाज पहुंचा सकता है, लेकिन सत्य की समझ नहीं। सोशल मीडिया पहचान दिला सकता है, लेकिन विश्वसनीयता अर्जित नहीं कर सकता। सच्ची पत्रकारिता आज भी वही है, जो दशकों पहले थीं तथ्यों की पुष्टि, निष्पक्षता, जनहित, संवेदनशीलता और सत्ता से सवाल पूछने का साहस। तकनीक इस यात्रा का साधन हो सकती है, उसका विकल्प नहीं। यदि पत्रकारिता में प्रशिक्षण की जगह शॉर्टकट, तथ्य की जगह सनसनी, जनहित की जगह प्रचार और जिम्मेदारी की जगह केवल लोकप्रियता का आकर्षण हावी हो गया, तो आने वाले समय में पत्रकारों की संख्या भले बढ़ जाए, लेकिन पत्रकारिता का स्तर लगातार गिरता जाएगा। लोकतंत्र को कैमरे वाले चेहरे नहीं, बल्कि सच लिखने और सच बोलने का साहस रखने वाले पत्रकार चाहिए। मोबाइल पत्रकार बना सकता है, लेकिन पत्रकारिता नहीं सिखा सकता। पत्रकारिता आज भी सीखनी पड़ती है, जीनी पड़ती है, और हर दिन अपने आचरण से साबित करनी पड़ती है।

सपा-कांग्रेस से सावधान रहें, विरासत और विकास दोनों की विरोधी : सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाराबंकी में ५४२ करोड़ रुपये से अधिक की ८२ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों दल विरासत, विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के जन्मजात विरोधी हैं। उन्होंने लोगों से इन दलों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि इनके शासन में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट होती थी।

मुख्यमंत्री ने लोधेश्वर महादेव मंदिर क रिडोर, केडी सिंह बाबू की हवेली के संरक्षण और बाराबंकी की सांस्कृतिक विरासत के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को नई पहचान दे रही है। उन्होंने लोधेश्वर महादेव मंदिर तक जाने वाली सड़क को फोरलेन बनाने और भव्य प्रवेश द्वार के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए। योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ने से युवाओं को रोजगार मिल रहा है और बाराबंकी को स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) से जुड़ने का लाभ मिलेगा, जिससे जिले के विकास को नई गति मिलेगी।

कांवड़ यात्रा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्य सचिव और डीजीपी ने सीमावर्ती राज्यों संग की हाई लेवल समीक्षा

लखनऊ/मेरठ। आगामी कांवड़ यात्रा-२०२६ को सकुशल, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार

को मुख्य सचिव एस.पी. गोयल और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्णा ने मेरठ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडलों के साथ-साथ उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान 'जीरो इंसीडेंट, जीरो एक्सीडेंट' के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाए तथा सभी विभाग अपने दायित्वों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कांवड़ मार्गों पर साफ-सफाई, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाएं, बाइक एम्बुलेंस, अस्पतालों में पर्याप्त बेड, ट्रैफिक प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, सड़क मरम्मत, मोबाइल शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, जल निकासी और प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ शिविरों के लिए अग्नि सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन कराने पर भी जोर दिया। डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से तत्काल और प्रभावी ढंग से निपटा जाए। उन्होंने असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने, सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक खबर और फेक नैरेटिव फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीजे संचालन सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप हो तथा डीजे प्रतियोगिता, बिना साइलेंसर वाले वाहन, स्टंटबाजी और अन्य अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। बैठक में विभिन्न मंडलों के अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से यात्रा मार्गों की तैयारियों और संभावित चुनौतियों की जानकारी दी। अधिकारियों को सीमावर्ती राज्यों के साथ बेहतर समन्वय, सूचना के त्वरित आदान-प्रदान और प्रभावी संचार व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के बाद मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने मेरठ स्थित बाबा औघड़नाथ मंदिर पहुंचकर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा जलाभिषेक भी किया। बैठक में एडीजी भानु भास्कर, आयुक्त मेरठ मंडल भानु चंद्र गोस्वामी, डीआईजी कलानिधि नैथानी, मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह, एसएसपी अविनाश पांडे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सीमावर्ती राज्यों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

घोसी चीनी मिल की तैयारियां समय पर पूरी हों: ए.के. शर्मा

लखनऊ/मऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आगामी पेराई सत्र को लेकर घोसी सहकारी चीनी मिल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मिल परिसर का भ्रमण कर प्लांट, मशीनरी, मानव संसाधन, संविदाकर्मियों की उपलब्धता, आंतरिक सड़कों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मिल के संचालन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए तथा किसानों को बेहतर सुविधाएं

उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने महाप्रबंधक को मिल के आधुनिकीकरण, आवश्यक मरम्मत, मशीनों के उन्नयन, मानव संसाधन, संविदाकर्मियों की व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार सहकारी चीनी मिलों को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाकर उनकी पेराई क्षमता बढ़ाने तथा संचालन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे किसानों को उनकी उपज का समय पर लाभ मिल सके।

जनस्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर

लखनऊ। लखनऊ छावनी क्षेत्र में जनस्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण पहल की गई। लखनऊ छावनी बोर्ड और जिला

स्वास्थ्य समिति, लखनऊ के बीच 'सहयोगात्मक स्वास्थ्य पहलों' के माध्यम से जनस्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी विशाख जी ने कहा कि विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उन्होंने इस पहल को जनहित में महत्वपूर्ण बताते हुए विश्वास जताया कि इससे छावनी क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने बताया कि एमओए के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, विशेष स्वास्थ्य शिविर और अन्य जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नीता मेमोरियल पॉलीक्लिनिक के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को आधुनिक और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उप प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.सी. जोशी एवं लेडी मेडिकल ऑफिसर डॉ. मेघा गुप्ता ने पॉलीक्लिनिक में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, आधुनिक उपकरणों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास संबंधी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्नयन के बाद नागरिकों को व्यापक, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.बी. सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, डॉ. ए.पी. सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप प्रताप सिंह, छावनी बोर्ड के नामित सदस्य प्रमोद शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अधिकारियों ने इसे लखनऊ छावनी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा अवसंरचना के विकास और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम बताया।

सहकारिता किसानों को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम: ए.के. शर्मा

लखनऊ/मऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ के मधुबन में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की नई शाखा भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने नए भवन के निर्माण पर बैंक प्रबंधन, सहकारी समिति और क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय के गठन से किसानों को कम ब्याज पर ऋण, गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मंत्री ने किसानों से सहकारिता की भावना को मजबूत करने का आह्वान करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए। उन्होंने बताया कि घोसी सहकारी चीनी मिल के सुचारु संचालन के लिए सरकार अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर काम कर रही है। आगामी पेराई सत्र के

लिए वित्तीय व्यवस्था की जा रही है, जबकि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से मिल के आधुनिकीकरण की योजना भी तैयार की जा रही है। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने बार्क में वैज्ञानिक पद पर चयनित हिमांशु वर्मा को उनके आवास पहुंचकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

टोकन लेकर खाद के लिए समिति के चक्कर लगा रहे किसान सरवर की समस्या बताई जा रही

धौरहरा खीरी। सर्वर की समस्या के कारण पिछले १० दिनों से यूरिया वितरण प्रभावित होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है।टोकन लेकर रोजाना समिति के चक्कर लगा रहे कई किसानों को अब तक खाद नहीं मिल सकी है। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर बाद धौरहरा बी–पैक्स पर सर्वर चालू होने के बाद यूरिया वितरण शुरू हुआ, लेकिन किसानों का आरोप है कि वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उनका कहना है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही यूरिया दी गई, जबकि टोकन लेकर घंटों इंतजार करने वाले अधिकांश किसान खाली हाथ लौट गए। किसानों ने बताया कि धान की रोपाई व गन्ने व केले में यूरिया का छिड़काव करने के लिए यूरिया की तत्काल आवश्यकता है। खाद नहीं मिलने से फसलों की ग्रोथ व बढ़वार प्रभावित होने की चिंता सता रही है। किसानों ने वितरण व्यवस्था में सुधार करते हुए टोकन के अनुसार सभी किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है। समिति सचिव शिवा त्रिवेदी ने बताया कि सर्वर चालू होने के बाद टोकन नंबर के क्रम में यूरिया का वितरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वर की समस्या के कारण वितरण प्रभावित हुआ था। सर्वर सामान्य होने पर उपलब्ध स्टॉक के अनुसार किसानों को यूरिया दी जा रही है।

रसूलपुर में बी पैक्स का शुभारम्भ

(मनोज मिश्र/के०के शुक्ला) धौरहरा/लखीमपुर। क्षेत्र के किसानों के लिए बहुप्रतीक्षित बी–पैक्स (प्राथमिक बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति) का सोमवार को रसूलपुर में शुभारंभ किया गया। धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी तथा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विनीत मनार ने संयुक्त रूप से शिलापट्ट का अनावरण कर समिति का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि बी–पैक्स सहकारी समिति किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि समिति के माध्यम से किसानों को उर्वरक, प्रमाणित बीज, कषि ऋण सहित अन्य आवश्यक कृषि सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ग्रामीण विकास को भी नई गति मिलेगी।कार्यक्रम के दौरान किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही इस उम्मीद में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे कि उद्घाटन के साथ ही खाद का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने और अतिथियों के रवाना होने के बाद समिति का शटर बंद कर दिया गया। इससे खाद लेने पहुंचे किसानों को बिना खाद लिए ही वापस लौटना पड़ा। खाद वितरण न होने से कई किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि उद्घाटन के दिन ही वितरण शुरू कर दिया जाता तो दूर–दराज से आए किसानों को राहत मिलती।किसानों ने मांग की कि समिति में जल्द से जल्द नियमित रूप से खाद,बीज व अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें समय पर कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन मिल सकें। हालांकि किसानों का कहना है कि बी–पैक्स समिति की शुरुआत क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक पहल है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहां से खाद,बीज, कृषि ऋण एवं अन्य सहकारी सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध होंगी। जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

रघुनगर बनी वॉलीबॉल टूर्नामेंट की विजेता, पचपेड़ा को दी मात

लखीमपुर खीरी।' नागरिक कल्याण योजना के तहत 'तृतीय वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, सी समवाय चंदन चौकी' द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच आयोजित किया गया। फाइनल मुकाबला 'रघुनगर और पचपेड़ा' की टीमों के बीच खेला गया। रोमांचक मैच में 'रघुनगर की टीम विजेता' रही। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि ' अजय कुमार पांडेय, द्वितीय कमान अधिकारी' और 'दलजीत सिंह, सी समवाय प्रभारी' की उपस्थिति में मैच का आयोजन किया गया। दोनों

अधिकारियों ने विजेता टीम को बधाई दी और खेल भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस आयोजन में 'मुकेश वंशल मुखिया, मनोज कुमार, चंदन चौकी थाना प्रभारी' सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीण '१५०' और SSB कार्मिक ५०' सहित कुल '२०० लोगों' ने मैच का आनंद लिया। SSB अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ता है। साथ ही युवाओं को खेलों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है।

पुराना शिवालय नदी की जग में आने से ग्रामीणों में चिंता

धौरहरा खीरी। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ जालिमनगर और हौकना मटेरा क्षेत्र में कटान तेज हो गई है। जालिमनगर पुल के पास स्थित स्नान घाट व वर्षों पुराना ऐतिहासिक शिवालय अब नदी की जद में आ गया है, जिससे ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार तेज कटान से खेतों के साथ आबादी और संपर्क मार्ग पर भी खतरा मंडरा रहा है। हौकना मटेरा क्षेत्र में वन विभाग की कुछ जमीन भी नदी में समा चुकी है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग और प्रशासन से तत्काल बचाव कार्य शुरू कराने की मांग की है।

तहसीलदार आदित्य विशाल ने बताया कि कटान रोकने के लिए बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता को रिपोर्ट भेजी गई है। हालांकि प्रभावित क्षेत्र तटबंध के अंदर होने के कारण बचाव कार्य में तकनीकी दिक्कत आ रही है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो शिवालय और आसपास का क्षेत्र गंभीर खतरे में आ सकता है।

छोटी काशी को श्रावण के लिए संवारने निकले डीएम अंजनी कुमार सिंह, बोले- हर व्यवस्था हो चाक-चौबंद

लखीमपुर खीरी। आगामी श्रावण माह के दौरान छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं एवं कांवड़ यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारु व्यवस्थाओं के दृष्टिगत डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सोमवार को गोला गोकर्णनाथ स्थित छोटी काशी शिव मंदिर पहुंचकर निर्माणाधीन क रिडोर का औचक निरीक्षण किया, संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। व्यवस्थाओं की बारीकी से पड़ताल करते हुए साफ संदेश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने कार्यदायी संस्था यूपी–पीसीएल को निर्देश दिए कि श्रावण माह शुरू होने से पहले सभी जरूरी निर्माण और आवश्यक व्यवस्थाएं हर हाल में पूरी कर ली जाएं। एसडीएम को व्यक्तिगत निगरानी की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि कोई भी कार्य अधूरा न रहे और किसी प्रकार की शिथिलता सामने नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दर्शन मार्ग, साफ–सफाई,

सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े सभी इंतजाम समय से पहले पूरे कर लिए जाएं, ताकि छोटी काशी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को व्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण मिल सके। इस दौरान एसडीएम युगांतर त्रिपाठी, कार्यदाई संस्था यूपी–पीसीएल के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद डीएम अंजनी कुमार सिंह ने छोटी काशी के प्राचीन शिव मंदिर में पूरे विधि–विधान से पूजा–अर्चना की। उन्होंने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पुष्प अर्पित किए और जनपदवासियों की सुख–समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की प्रार्थना की।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः APAAR ID बनवाना पूरी तरह वैकल्पिक, अभिभावकों की अनुमति के बिना स्कूल नहीं बना सकेंगे आईडी

नई दिल्ली। देशभर के करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि **APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) ID** पूरी तरह वैकल्पिक (**Optional**) है और किसी भी छात्र का **APAAR ID** अभिभावकों की स्पष्ट सहमति के बिना नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (**CBSE**) को निर्देश दिया है कि वह उड़ीसा हाईकोर्ट के दिसंबर २०२५ के फैसले को पूरे देश में लागू करे। इसके तहत स्कूलों को सहमति पत्र (**Consent Form**) में अभिभावकों को 'ऑप्ट–आउट' (**APAAR ID** न बनवाने) का स्पष्ट विकल्प देना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने, प्रवेश लेने या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड या **APAAR ID** बनवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ब्लैम के सभी नियम और दिशा–निर्देश डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (**DPDP**) अधिनियम, २०२३ के अनुरूप होने चाहिए। यह मामला चार छात्रों के अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान

सामने आया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि सरकार भले ही **APAAR ID** को वैकल्पिक बता रही है, लेकिन व्यवहार में स्कूलों के माध्यम से इसे लगभग अनिवार्य बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को आधार और **APAAR ID** के लिए बाध्य करना शिक्षा के संवैधानिक अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है, इसलिए उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति–२०२० के तहत शुरू की गई **APAAR ID** योजना का उद्देश्य छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और प्रशासनिक सुधार लाना है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक पहल बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में डेटा सुरक्षा कानून और अभिभावकों की सहमति से समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब देशभर के स्कूल **APAAR ID** के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकेंगे और प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चे के लिए इस योजना से बाहर रहने (**Opt&Out**) का अधिकार मिलेगा।

वेंटिलेटर पर जिला अस्पताल मरीज और तीमारदार बेहाल

पर्चा काउंटर से लेकर लिफ्ट तक सब ध्वस्त, 2 काउंटर में से 1 बंद, दवा काउंटर पर स्टाफ नदारद

लखीमपुर खीरी। मोतीपुर ओयल स्थित जिला अस्पताल की हालत खुद गंभीर मरीज जैसी हो गई है। प्रशासनिक लापरवाही और बदइंतजामी के चलते दूर–दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आरोप है कि प्राचार्य 'वाणी गुप्ता' और सीएमएस की कथित लापरवाही से अस्पताल की बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। अस्पताल में पर्चा बनवाना भी एक बहुत बड़ा युद्ध जीतने जैसा है आभा कार्ड के चक्कर में लोग और परेशान होते हैं कहीं इंटरनेट की समस्या कहानी सरवर की समस्या जिसके चलते अस्पताल के पर्चा काउंटर पर सुबह से ही भारी भीड़ जमा हो जाती है। टोकन और पर्चे के लिए लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन २ काउंटर में से १ को बंद रखा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि सर्वर धीमा है। नतीजा ये है कि सुबह से दोपहर तक का समय सिर्फ पर्चा बनवाने में ही निकल जा रहा है। बुजुर्ग, दिव्यांग, पत्रकार और अस्पताल का स्टाफ तक पर्चे के लिए भटक रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के पर्चे न बन पाने से स्थिति और गंभीर हो गई है। मरीजों का सवाल है – 'अगर पर्चे में ही आधा दिन लग जाएगा तो डॉक्टर को कब दिखाएंगे?' अस्पताल परिसर में लगी सभी लिफ्ट खराब पड़ी हैं। तीन मंजिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को बार–बार सीढ़ियां चढ़–उतर कर आना–जाना पड़ रहा है। पैर फ्रैक्चर, दिल के मरीज, अ परेशन के बाद वाले और बुजुर्गों को वार्ड तक पहुंचाने में तीमारदारों की सांसें फूल रही हैं। मरीजों के लिए पीने के साफ पानी की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। शौचालय गंदगी से भरे हैं और आधे निर्माणाधीन हैं। अस्पताल परिसर में गंदगी और बदबू के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। इलाज की उम्मीद में आने वाले लोग यहां और बीमार महसूस कर रहे हैं। २० जुलाई २०२६ को दोपहर १२ बजे के बाद दवा वितरण काउंटर पर भी लापरवाही सामने आई। दवा बांटने वाले लड़के नदारद थे। सिर्फ एक फार्मासिस्ट अकेले ही मरीजों को दवा समझाकर दे रहे थे। इससे मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ा और उनका धैर्य जवाब देने लगा। स्थानीय लोगों और मरीजों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि मोतीपुर ओयल जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का तुरंत संज्ञान लिया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।

त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ पुलिस मुख्यालय में मृत मिले, आत्महत्या की आशंकाय जांच शुरू

अगरतलाध्नई दिल्ली। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (क्ळच्) अनुराग धनखड़ सोमवार को अगरतला स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में अपने कार्यालय में मृत पाए गए। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अनुराग धनखड़ १९९४ बैच के आईपीएस अधिकारी थे और उन्होंने मई २०२५ में त्रिपुरा के डीजीपी का पदभार संभाला था। उनका पैतृक संबंध उत्तर प्रदेश के बागपत से बताया जाता है। अपने लंबे पुलिस करियर के दौरान अनुराग

धनखड़ ने सीबीआई में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने नीरव मोदी बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच का नेतृत्व किया था और १९८४ सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (**SIT**) के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी सेवाएं दी थीं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मृत्यु के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, लखनऊ द्वारा १२२वां मंडी सचिव प्रशिक्षण का शुभारंभ

लखनऊ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (**DMI**), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा ४५ दिवसीय १२२वां मंडी सचिव

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (**MSTC**) का उद्घाटन आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हिमांशु पांडे (**IES**), मुख्य अभियंता, **CPWD** ने दीप प्रज्वलन कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने मंडियों के कुशल संचालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने में प्रशिक्षित मानव संसाधन की भूमिका पर बल दिया तथा प्रतिभागियों से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करने का आह्वान किया। निदेशालय की ओर से श्री भवेश कुमार जोशी, उप–कृषि विपणन सलाहकार ने मुख्य अतिथि एवं प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम मंडी प्रबंधन, विपणन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण तथा किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक होगा। इस अवसर पर निदेशालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीं श्री जितेन्द्र सिंह, श्री एम. जे. अहमद एवं श्री अनुपम कुमारेंने भी प्रतिभागियों को सक्रिय सहभागिता हेतु प्रेरित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान से आए मंडी सचिव भाग ले रहे हैं। उन्हें कृषि विपणन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, १४ दिवसीय अखिल भारतीय अध्ययन भ्रमण भी आयोजित होगा, जिससे प्रतिभागियों को विभिन्न राज्यों की उन्नत विपणन व्यवस्थाओं का अनुभव प्राप्त होगा। यह प्रशिक्षण प्रतिभागियों को अपने–अपने राज्यों में कृषि विपणन प्रणाली के सुधार एवं सु ढ़ीकरण में प्रभावी योगदान देने हेतु सक्षम बनाएगा।

तीन दिन बाद भी मौत की गुत्थी नहीं सुलझी, DNA रिपोर्ट का इंतजार, वनकर्मी रात दिन भीग भीग कर रहे गस्त

गोला गोकर्णनाथ खीरी,। दक्षिणी खीरी वन प्रभाग की महेशपुर रेंज के ग्राम झाऊपुर में किसान जयप्रकाश शर्मा के गन्ने के खेत में मिले मानव कंकाल के मामले में मौत का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को मिले कंकाल की पहचान तुलमेलगंज निवासी ३५ वर्षीय अनिल कुमार पुत्र जुगुल किशोर के रूप में हुई थी। प्रथम दृष्टया इसे बाघ के हमले से हुई मौत माना जा रहा था। हैदराबाद थाना प्रभारी सुनील मलिक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने क्छ। सैंपल को प्रयोगशाला भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में बाघ की दहशत बनी हुई है। किसान समूह में ही खेतों की ओर जा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही है। वन विभाग ने दिया मदद का भरोसा रेंजर निर्भय प्रताप शाही के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ग्राम प्रधान पति आलोक जायसवाल की मौजूदगी में १० हजार रुपये की तात्कालिक सहायता प्रदान की थी। विभाग ने आश्वासन दिया है कि सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर **WWF** योजना के तहत परिवार को ५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। वहीं डीएफओ तपस मिहिर ने रविवार देर रात करीब ६ बजे स्वयं मौके पर पहुंचकर ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र में बाघ की लोकेशन ट्रेस कराई। इस दौरान एसडीओ, रेंजर मोहम्मद उमर, डिप्टी रेंजर अखिलेश सिंह, वन दरोगा रोहित श्रीवास्तव, विजय सिंह, मित्रपाल तोमर, प्रज्ज्वल सहित तमाम बीट वाचर मौजूद रहे। वही वन कर्मियो ने दिन रात भारी बरसात के बाबजूद भी पूरे क्षेत्र मे बराबर गस्त कर रहे है इसके साथ अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सतर्क रहें और खेतों में अकेले न जाएं।

मुख्यमंत्री ने लोधेश्वर महादेव का दर्शन–पूजन कर किया अभिषेक

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोधेश्वर धाम में दर्शन–पूजन कर महादेव का अभिषेक किया। सीएम ने बाबा भोलेनाथ की आरती भी उतारी और ईश्वर से सुखी, स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की।

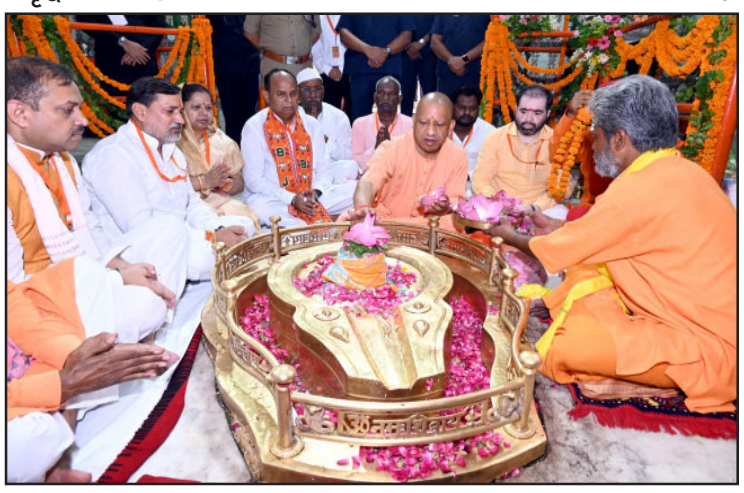

मंदिर परिसर में डमरू वादन संग उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय कलाकारों की हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने दर्शन–पूजन के उपरांत निर्माणाधीन कॉरिडोर का अवलोकन भी किया और कार्यों के निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश भी दिए। दर्शन–पूजन के बाद मुख्यमंत्री लोधेश्वर महादेव मंदिर के पीछे स्थित प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने यहां बच्चों का अन्नप्राशन किया और उन्हें खिलौने देकर दुलारा–पुचकारा। सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों से उनके मॉडल के बारे में जानकारी ली। साथ ही बच्चों को चॉकलेट भी दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल प्रदान की। बाराबंकी के विकास को लेकर लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। सीएम के हाथों इन्हें मिला सम्मान. ..शिवशंकर वर्मा– कृष यंत्र के तहत चाबी, प्रमाण पत्र व ४ लाख का चेक, छाया देवी– कृषि यंत्र के तहत चाबी, प्रमाण पत्र व ४ लाख का चेक, मोहसिन मतीन– प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के तहत १० लाख का चेक, मुकेश कुमार– प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के तहत ३. १० लाख का चेक, शांति देवी– विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत सिलाई का टूल किट, नितेश वर्मा– सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ५ लाख का चेक, मो. आलम– ओडीओपी के तहत २१ लाख का चेक ,हेमकरण माथुर– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ३.६० करोड़ से अधिक का चेक, हर्षिता वर्मा– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत को १५ लाख का चेक, प्रमेंद्र विक्रम सिंह– मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत ११. ८० लाख से अधिक का चेक, आरती देवी–मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र, गायत्री देवी– मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृत पत्र, आरती व अशोक कुमारी सिंह– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सामुदायिक निवेश निधि के लिए ३.१६ करोड़ से अधिक का चेक।

जंतर-मंतर से संसद कूच के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों में कड़े इंतजाम।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर–मंतर से संसद की ओर प्रस्तावित मार्च के दौरान राजधानी दिल्ली में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की, जिसके दौरान झड़प और हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कुछ विपक्षी नेताओं को भी सुरक्षा बलों ने आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान धक्का–मुक्की की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के दौरान एक युवक का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह लाठीचार्ज के बीच पुलिस के सामने डटा दिखाई दिया। वीडियो में युवक पुलिस से ष्मारो, और मारोष कहते हुए नजर आता है। हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली मेट्रो के पांच प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना

करना पड़ा। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और यात्रियों ने बैरिकेडिंग के बीच मेट्रो परिसरों में प्रवेश करने की भी कोशिश की। पुलिस ने संसद क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे और बिना अनुमति मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान हालात पर कड़ी निगरानी रखी गई।

मानसून सत्र के बीच दिल्ली में प्रदर्शन से हंगामा, संसद क्षेत्र हाई अलर्ट परय कई प्रदर्शनकारी हिरासत में

नई दिल्ली।'' संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को राजध ाानी दिल्ली में प्रदर्शन के चलते कई इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों के संसद की ओर मार्च के प्रयास को देखते हुए ''संसद क्षेत्र, कर्तव्य पथ और आसपास के अति संवेदनशील इलाकों'' में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रदर्शन के मद्देनजर संसद के प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और कई मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्थानों पर कार्रवाई की, जिसमें ''लाठीचार्ज'' भी किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को ''हिरासत में लिया गया''। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कई मार्गों पर यातायात नियंत्रित किया और भीड़ को हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया। चूंकि संसद के भीतर विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मौजूद थे, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने संसद परिसर और आसपास के क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कानून–व्यवस्था बनाए रखने और संसद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वहीं, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।

ऑपरेशन कवच का पहला वारः ६६ वाहनों पर कार्रवाई, १६ बसें–कार सीजय नियम तोड़ने वालों पर परिवहन विभाग की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक

लखनऊ। राजधानी में अनधिंत रूप से संचालित यात्री वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए परिवहन विभाग द्वारा चलाया जा रहा 'ऑपरेशन कवच' पहले ही दिन प्रभावी नजर आया। सोमवार को चले विशेष अभियान में ६६ वाहनों का चालान किया गया, जबकि १६ वाहनों को सीज (निरुद्ध) कर दिया गया। इनमें १४ बसें और २ कार/आर्टिगा शामिल हैं। कार्रवाई से अवैध संचालन करने वाले वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया। मुख्यालय के निर्देश पर २० से २१ जुलाई तक चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आलमबाग चौराहा–नहरिया रोड, पीजीआई मार्ग, लखनऊ– सुल्तानपुर रोड स्थित अहिमामऊ– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा पॉलीटेक्निक–कमता–अयोध्या मार्ग पर संयुक्त टीमें तैनात की गईं। परिवहन विभाग, राज्य कर विभाग, परिवहन निगम और यातायात पुलिस के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से वाहनों की गहन जांच की। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। चार स्लीपर बसों की छत पर व्यावसायिक माल ढोया जा रहा था, जो यात्री वाहनों के परमिट की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इन बसों को तत्काल सीज कर राज्य कर विभाग ने भी माल की जांच करते हुए अलग से कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा चार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसें ऐसी मिलीं जो अपने गृह राज्य से संचालित होने के बजाय दो अन्य राज्यों के बीच नियमित संचालन कर रही थीं। यह ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की शर्तों का

उल्लंघन है। परिवहन विभाग ने ऐसे मामलों में संबंधित परमिट प्राधिकरणों को कठोर कार्रवाई की संस्तुति भेजने का निर्णय लिया है। परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अभियान सड़क सुरक्षा, कर चोरी पर रोक और वैध परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि यदि ऑपरेशन कवच केवल दो दिनों तक सीमित न रहकर नियमित और निरंतर अभियान के रूप में चलाया जाए, तो अवैध बस संचालन, परमिट उल्लंघन और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यह अभियान उप परिवहन आयुक्त, लखनऊ परिक्षेत्र राधेश्याम तथा संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रभात पाण्डेय के निर्देशन में संचालित किया गया। अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव एवं आस्था बंसल, रायबरेली के यात्रीध्मालकर अधिकारी विक्रांत सिंह, उन्नाव के विनय कुमार पाण्डेय, हरदोई के खेमानंद पाण्डेय, सीतापुर के आब्दीन अहमद सहित राज्य कर विभाग, परिवहन निगम एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। यदि अभियान की यही गति और सख्ती आगे भी बनी रही तो अवैध यात्री वाहन संचालन पर प्रभावी अंकुश लगने के साथ–साथ यात्रियों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भूसा-चारा उपलब्ध कराएंः धर्मपाल सिंह

लखनऊ। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध ा विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधि ाकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ एवं जलभराव संभावित क्षेत्रों में गोवंश एवं अन्य पशुओं के लिए भूसे और हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वर्षा ऋतु को देखते हुए गो–आश्रय स्थलों

का चिन्हांकन, पशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। विधान भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने २० जुलाई से ३ अगस्त तक चलने वाले विशेष गोवंश सुपुर्दगी अभियान को मिशन मोड में संचालित करने, अधिक से अधिक पात्र किसानों व पशुपालकों को योजना से जोड़ने तथा लाभार्थियों को समय पर भरण–पोषण राशि उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं एवं कुपोषित परिवारों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और विभागीय योजनाओं की नियमित म निटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत करने, दुग्ध संग्रहण एवं कोल्ड चेन व्यवस्था सु ढ़ करने तथा निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

जीरो पॉवर्टी अभियान की समीक्षा, सीएम योगी बोलेंहर पात्र परिवार तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत अब तक १२.५० लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को स्टेट ट्रांसफ मेंशन कमीशन की बैठक में अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द अंत्योदय राशन कार्ड से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो पॉवर्टी अभियान का उद्देश्य प्रदेश के सबसे जरूरतमंद और वंचित परिवारों की पहचान कर उन्हें गरीबी से बाहर निकालना है। इसके लिए विशेष टीम गठित कर अभियान को और प्रभावी बनाया जाए तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी

पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वेक्षण के आधार पर पात्र परिवारों को शीघ्र अंत्योदय राशन कार्ड से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना के कार्यों में तेजी लाने, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की औपचारिकताएं जल्द पूरी करने और चिकित्सा महाविद्यालयों व होटलों में फायर एनओसी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था, फीडरों की ओवरलोडिंग, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सांसद एवं विधायक निधि से चल रहे विकास कार्यों और डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी हों और उनका लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचे।

सरकार की नीतियों के खिलाफ सपाइयों ने सड़क पर उतरकर आक्रामक प्रदर्शन किया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ एक अनोखा और आक्रामक प्रदर्शन किया। सपा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने हाथों में

किताबें थामी हुई थीं, जिन पर सांकेतिक रूप से एक खिलौना बुल्डोजर रखा हुआ था और उसे लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। कार्यकर्ता 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' पर हो रही कार्रवाई और लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता 'सोनम वांगचुक' के समर्थन में बैनर–पोस्टर लेकर विधानसभा की तरफ बढ़े, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी जैसे ही विधानसभा के करीब पहुंचे, मुस्तैद पुलिस बल ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर सपा कार्यकर्ता विरोध स्वरूप सड़क पर ही लेट गए। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और करीब १० से १२ कार्यकर्ताओं को जबरन उठाकर पुलिस बस में बैठा दिया। हिरासत में लिए गए इन प्रदर्शनकारियों को तुरंत 'इको गार्डन' धरना स्थल भेज दिया गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज ५ मिनट के भीतर प्रदर्शन स्थल को खाली करा लिया। प्रदर्शन में शामिल सपा नेता उदय सिंह ने मीडिया से बातचीत में सीधे सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा आज जौहर यूनिवर्सिटी पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इनकी पूरी राजनीति सिर्फ यादवों और इस शिक्षण संस्थान के विरोध पर टिकी है। अगर निष्पक्ष जांच हो, तो बीजेपी के कई बड़े कार्यालयों के नक्शे भी पास नहीं मिलेंगे। वहीं, प्रदर्शनकारी मनीष कुमार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार में पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। यह सरकार पूरी तरह से शिक्षा विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रही है, जिसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं।

लखनऊ अग्निकांड वाली इमारत पर चला बुलडोजर, मालिक ने शुरू कराया ध्वस्तीकरण

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अलीगंज सेक्टर–डी स्थित उस व्यावसायिक भवन का ध्वस्तीकरण सोमवार से शुरू हो गया, जहां हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड ने कई लोगों की जान ले ली थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद भवन स्वामी ने स्वयं अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू कर दिया है। एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि अलीगंज के सेक्टर–डी स्थित भूखंड संख्या एमएस–१०२ पर वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला व अन्य द्वारा बिना वैध अनुमति के व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया था। इस मामले में २३ जून २०२६ को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २७(१) के तहत नोटिस जारी कर १५ दिन के भीतर निर्माण की वैधता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया था। प्रकरण की सुनवाई ७, ८ और ९ जुलाई को विहित प्राधिकारी की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच के बाद १०

जुलाई २०२६ को न्यायालय ने निर्माण को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया। भवन स्वामी को २५ जुलाई २०२६ तक स्वयं अवैध निर्माण हटाने का समय दिया गया था। एलडीए के अनुसार, निर्धारित समय सीमा पूरी होने से पहले ही सोमवार को भवन स्वामी की ओर से अवैध ढांचे को तोड़ने का कार्य शुरू करा दिया गया। सूचना मिलने पर प्रवर्तन जोन–४ के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। जोनल अधिकारी ने निर्माण पक्ष को बरसात के मौसम को देखते हुए सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ध्वस्तीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी। एलडीए ने कहा है कि २५ जुलाई के बाद स्थल का दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि आदेश का पूर्ण पालन नहीं मिला तो प्राधिकरण स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

बंद कमरे में पति–पत्नी के शव मिलने से हड़कंप, छह महीने पहले हुई थी शादी

रायबरेली। जिले के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। शादी के महज छह महीने बाद पति–पत्नी ने कथित तौर पर एक ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता उस समय चला जब परिजन खेत से लौटे और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, पखरामऊ गांव निवासी अभिनव कुमार (२५) का विवाह करीब छह माह पहले गुरुबक्शगंज थाना क्षेत्र के अघोरा गांव निवासी रूपाली साहू से हुआ था। परिजनों का कहना है कि विवाह के बाद से दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था।

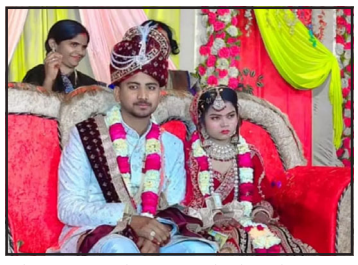

सोमवार को भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। उस समय परिवार के अन्य सदस्य खेतों में काम करने गए थे। घर लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर दोनों पति–पत्नी एक ही पंखे से फंदे पर लटके मिले। परिजन तुरंत दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही डलमऊ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।कोतवाल राघवन कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पति–पत्नी के आपसी विवाद के बाद आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा।

प्रयागराज में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कुछ ही देर की तेज बारिश से शहर की प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं। मुख्य बाजार समेत कई इलाकों में जलभराव के कारण आवागमन बाधित हुआ, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फूलपुर में बारिश का पानी कई दुकानों के भीतर तक घुस गया, जिससे व्यापारियों को आनन–फानन में अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर रखना पड़ा। कई दुकानों में पानी घुसने से भारी नुकसान की आशंका है। बाजार में खरीदारी के लिए आए लोगों को जलभराव के बीच से गुजरना पड़ा। कई स्थानों पर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। फूलपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। कई गांवों में खेतों में पर्याप्त पानी भरने से किसानों में खुशी का माहौल है। धान की रोपाई कर चुके किसानों ने इस बारिश को फसलों के लिए बेहद फायदेमंद बताया। किसानों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से बारिश की कमी के कारण खेतों में नमी की कमी थी, लेकिन अब हुई बारिश से धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों को पर्याप्त पानी मिल गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कस्बे में हर वर्ष बारिश के दौरान जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ऐसी ही स्थिति उत्पन्न

होती है। नालियों की समय पर सफाई न होने और प्रभावी जल निकासी व्यवस्था के अभाव में बारिश का पानी सड़कों और बाजारों में जमा हो जाता है।लोगों ने नगर पंचायत से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने, नालियों की नियमित सफाई और बेहतर जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि बरसात के मौसम में आमजन और व्यापारियों को राहत मिल सके।

सुरक्षित मातृत्व में यूपी की बड़ी उपलब्धि, १६ जिलों में शून्य गैर–संस्थागत प्रसव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने सुरक्षित मातृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के १६ जिलों में अप्रैल से जून तक लगातार तीन माह के दौरान सभी प्रसव स्वास्थ्य संस्थानों में हुए। इस अवधि में इन जिलों में घर या अन्य स्थान पर एक भी गैर–संस्थागत प्रसव दर्ज नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसे जनजागरूकता, मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं और आशा, एएनएम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समन्वित प्रयासों का परिणाम बताया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवेल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला महिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में प्रसूति सेवाओं को लगातार सुदृढ़ किया गया है। आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षित स्टाफ, दवाओं की उपलब्धता और बेहतर

रेफरल व्यवस्था के कारण संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) और नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) में और कमी आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार अस्पताल में प्रसव होने से जटिल परिस्थितियों में मां और नवजात, दोनों की जान बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। विभाग का कहना है कि गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, नियमित प्रसवपूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान, आशा कार्यकर्ताओं का घर–घर संपर्क, १०८ एंबुलेंस सेवा और जननी सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। एचएमआईएस के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, वाराणसी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गाजीपुर, शामली, गाजियाबाद, हाथरस, इटावा, महोबा और कौशांबी में अप्रैल से जून के बीच एक भी गैर–संस्थागत प्रसव दर्ज नहीं हुआ।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने २ छात्रों को किया निलंबित, हॉस्टल भी छूटा

लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया बाधित करने, न्यायालय में कागज फाड़कर फेंकने और अपशब्दों का प्रयोग करने वाले दो छात्रों को लखनऊ विश्वविद्यालय ने निलंबित कर

दिया है। विधि तृतीय वर्ष के छात्र प्रबल प्रताप सिंह और चंद्रभान विधि द्वितीय वर्ष के छात्र को विश्वविद्यालय ने निलंबित करते हुए छात्रावास सुविधा समाप्त कर दी है और विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय में लखनऊ विश्वविद्यालय के दोनो छात्रों ने न्यायपालिका की प्रक्रिया बाधित करने के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने छात्रों के खिलाफ ११ जुलाई को एफआईआर दर्ज की थी। जिसकी सूचना मिलते ही लखनऊ विश्वविद्यालय ने १५ जुलाई को एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय ने दोनों छात्रों को जांच अवधि तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में स्थित विधि संकाय में जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम आई थी। जो इन दोनों छात्रों के बारे में जानकारी हासिल कर वापस चली गई। विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक और प्रतिष्ठित न्यायिक संस्थान के गरिमा के प्रतिकूल आचरण करने को लेकर छात्रों पर कठोर कार्रवाई है।

डीसीजीआई ने 'क्यूडेंगा' को दी बाजार में उतारने की मंजूरी

नयी दिल्ली। डेंगू के पहले स्वदेशी टीके को बाजार में उतारने के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) की मंजूरी मिल गयी है। क्यूडेंगा नाम का यह टीका टाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया ने बनाया है। डीसीजीआई ने न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल्स (एनडीसीटी) नियम, २०१६ के सीटी–२० प्रावधान के तहत चार से ६० वर्ष के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए इस टीके को बाजार में उतारने की मंजूरी दी है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि क्यूडेंगा को मिली यह मंजूरी देश में डेंगू की रोकथाम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश में मंजूरी पाने वाला डेंगू का पहला टीका है। किसी को पहले डेंगू का संक्रमण हुआ हो या नहीं, उसे यह टीका लगाया जा सकता है। डेंगू मच्छरों के जरिये फैलने वाला एक वायरसजनित रोग है।

'इश्कनामा' के 'नरक' को शहनाज गिल ने दी अपनी आवाज

मुम्बई। अभिनेत्री और गायिका शहनाज गिल ने अपनी आगामी फिल्म 'इश्कनामा' के चर्चित गीत 'नरक' का स्पेशल कवर वर्जन पेश किया है। फिल्म की रिलीज से पहले जारी किए गए इस कवर वर्जन में शहनाज ने अपनी आवाज और ज्योतिका ने मूल गीत को बेहद खूबसूरती से पेश किया है और उन्होंने इसे अपने अंदाज में गाने की कोशिश की है। शहनाज गिल इससे पहले भी पंजाबी और हिंदी संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं। इस कवर वर्जन के

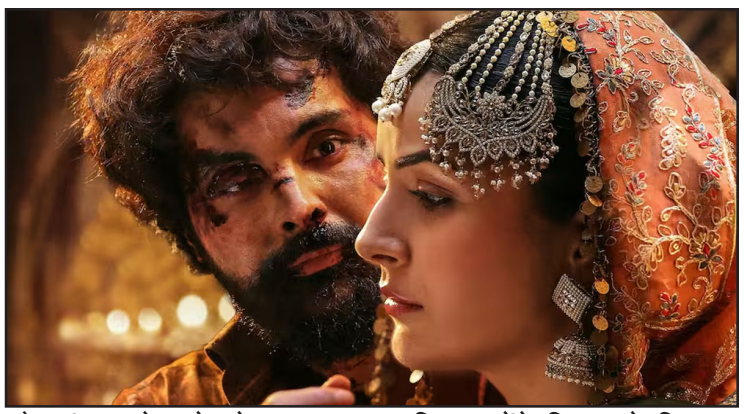

और अंदाज से गाने को एक नया भाव दिया है। मूल गीत को बी प्राक और ज्योतिका टांगरी ने आवाज दी है। जानी के लिखे और कंपोज किए गए इस गीत में फिल्म के मुख्य किरदार नसीमा और निम्मा के बीच दर्द, तड़प और अनकहे प्यार को दर्शाया गया है। फिल्म में नसीमा की भूमिका निभा रहीं शहनाज ने कहा कि 'नरक' उनके पसंदीदा गानों में से एक है और इसका अपना वर्जन रिकॉर्ड करना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि बी प्राक जरिए उन्होंने फिल्म के किरदार और कहानी से अपने भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाया है। 'इश्कनामा' निम्मा और नसीमा की असाधारण सच्ची कहानी से प्रेरित फिल्म है, जिसकी कहानी वर्ष १९८१ से १९८८ के बीच भारत–पाकिस्तान सीमा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में शहनाज गिल, जय रंधावा और सौरभ सचदेवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। अरविंदर एस. खैरा के निर्देशन में बनी यह फिल्म २४ जुलाई २०२६ को भारत, कनाडा और ब्रिटेन के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बटवारा १९४७ का नया टीजर रिलीज

मुम्बई। आमिर खान प्रोडक्शंस की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बटवारा १९४७' का नया टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म का मोशन पोस्टर और कैरेक्टर पोस्टर्स पहले ही चर्चा में से एक, देश के विभाजन, की झलक प्रस्तुत करता है। फिल्म में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर

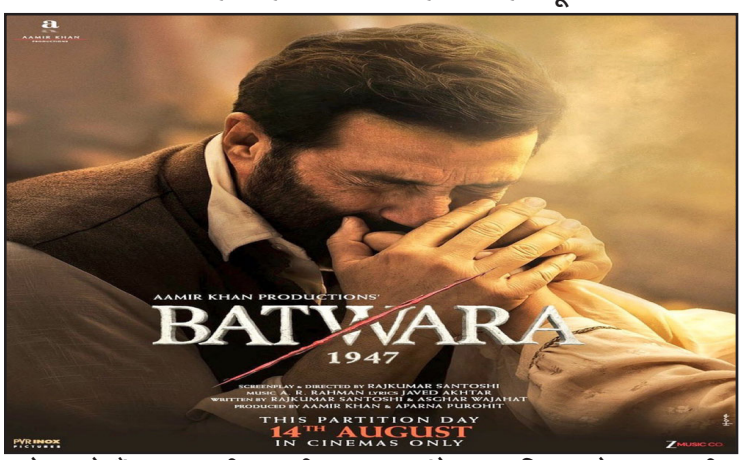

बटोर चुके हैं। अब जारी नए टीजर में बटवारे के दौर की त्रासदी, साहस, बलिदान और इंसानी जज्बे की झलक देखने को मिलती है। टीजर में सनी देओल एक ऐसे निडर व्यक्ति के किरदार में नजर आते हैं, जो विषम परिस्थितियों के बीच अपने परिवार की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा रहता है। नफरत और हिंसा के माहौल में उनका किरदार साहस और मानवता का संदेश देता दिखाई देता है। रोमांच से भरपूर यह टीजर भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और दर्दनाक अध्यायों आएंगे। इस फिल्म के साथ करीब तीन दशक बाद निर्देशक राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी फिर साथ आई है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म का निर्माण आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है। 'बटवारा १९४७' १४ अगस्त, २०२६ को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566
सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक